जेट विमान, हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार

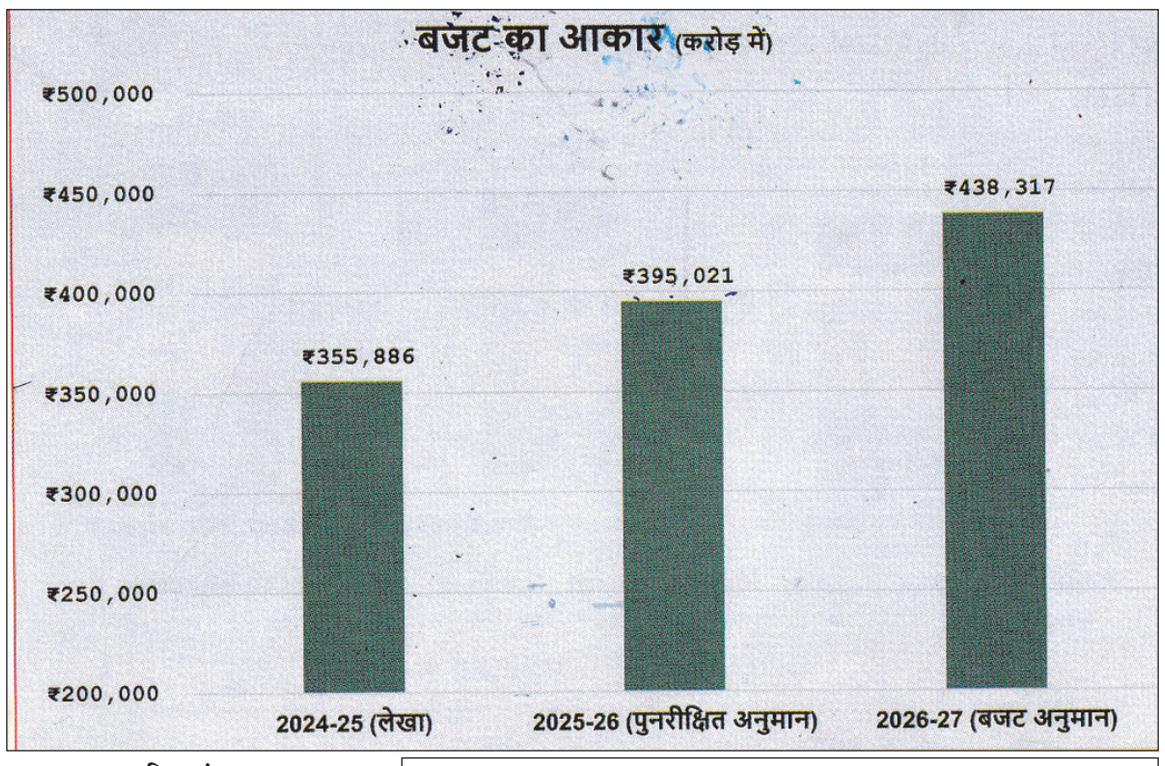

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 फरवरी. राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर भी खरीदेगी. अभी सरकार को वीआईपी के मूवमेंट के लिए किराए पर जेट लेना पड़ता है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद राज्य सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है.

इसलिए ही बजट में नया जेट खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 180 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है.

बजट में ये भी खास

- पीएम कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 3 हजार करोड़ की लागत के एक लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे.
- कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ में सखी-निवास का निर्माण.
- मुख्यमंत्री मजरा- टोला सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के जिलए 800 करोड़ का इंतजाम.
-एक हजार 766 पुल और पुलियों के निर्माण की 4 हजार 572 करोड़ की क्षतिग्रस्त पुलों का पुर्ननिर्माण योजना मंजूर. नए बजट में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- सिंहस्थ महापर्व के कामों के लिए 3 हजार 60 करोड़ का इंतजाम.

विधायकों का स्वेच्छा अनुदान भी नहीं बढ़ेगा

बजट में विधायकों के स्वेच्छा अनुदान मद में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं हुई है. विधायकों के लिए इस मद में 173 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं विधायकों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि भी यथावत रखी गई है. इस मद में फिलहाल 575 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है.

मतदाता सूची तैयार करने 132 करोड़ रुपए खर्च होंगे

मतदाता सूची तैयार करने और मुद्रण कराने के लिए बजट में 132 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है. वहीं न्यायालय भवनों के निर्माण पर 301 करोड़ रुपए, उच्च न्यायालय भवन और आवासीय परिसरों के निर्माण पर 105 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ग्राम न्यायालय के लिए भी 87 करोड़ रुपए मिलेंगे.

आपदा प्रबंधन के लिए 1449 करोड़ का प्रावधान

राजस्व विभाग के तहत आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए 1449 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं तहसील, जिला और संभाग के भवन और आवासीय परिसरों के निर्माण पर 411 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ओला पीड़ितों को राहत के लिए बजट में 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना होगी

गृह विभाग के तहत राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना होगी, इस पर 129 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अपराध अनुसंधान विभाग के तहत 429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. गृह विभाग के सामान्य व्यय जिला पुलिस के लिए 7250 करोड़ और सामान्य व्यय विशेष पुलिस के लिए 2352 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है.

सीएम स्वेच्छानुदान के लिए 200 करोड़

बजट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के लिए 78 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है. मंत्रालय के लिए भी 270 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ये राशि मंत्रालय के रिनोवेशन पर खर्च होगी.

प्रावधान - प्रतिक्रियाएं

मेट्रो रेल के काम पर 656 करोड़ खर्च करेगी सरकार

भोपाल. राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के विस्तार कार्यक्रम पर 656 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इन दोनों ही शहरों में पहले चरण का काम हो गया है, अब दूसरे चरण का काम चल रहा है. इस चरण का काम भी वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. नगरीय विकास एवं विकास विभाग के तहत सिंहस्थ से जुड़े कार्यों के लिए 3060 करोड़ रुपए तो मिलियन प्लस शहर अमृत 2.0 के लिए 1418 करोड़, निकायों में मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के तहत 1058 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी. कायाकल्प अभियान के लिए 200 करोड़, गीता भवनों के निर्माण के लिए 60 करोड़ और अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सीएम वृंदावन ग्राम योजना के लिए 104 करोड़ मिलेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत सीएम वृंदावन ग्राम योजना के लिए 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार करोड़, पीएम सड़क योजना की सड़कों के मरम्मत और उन्नयन पर 1285 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण 900 करोड़ में किया जाएगा. पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइयों को मानदेय के लिए 640 करोड़ पीएम जनमन सड़क योजना के लिए 603, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 603 और सीएम आवास मिशन के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बजट में सामाजिक न्याय विभाग के लिए 2343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पर 1152 करोड़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पर 400 करोड़ रुपए, सीएम कन्या विवाह पर 262 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

सुरेश राजे विधायक डबरा

कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे ने बताया कि इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है. सिर्फ खोखले आंकड़े हैं. सरकार कहती है कि हमने कोई भी नया टेक्स नहीं लगाया है लेकिन यह बताये कि नौजवानों को क्या दिया किसानों और व्यापारियों को क्या दिया. चौहत्तर हजार करोड़ के घाटे का बजट है. सरकार प्रदेश को कर्ज के दल दल में फसा चुकी है .सरकार ने जो कर्ज ले रखा उसकी भरपाई कर रही है. इस बजट से जनता को निराशा हाथ लगी है इस लिए हम इस बजट का विरोध करते हैं.

अनुभा मुंजारे की प्रतिक्रिया

कांग्रेस की बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट जो पेश किया गया है यह सिर्फ लोक लुभावना है हकीकत से कोई लेना देना नहीं है. सपना दिखाने वाला है .अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाओं को रोजगार दिया है या उनके लिए लघु उद्योग खोलने के लिए कितने प्रयास किए गए. सरकार मंहगाई पर रोक लगाने में असफल रही है महिलाओं का संबंध किचिन से अधिक होता है तो रसोई गैस राशन सहित अन्य सामान महंगे हुए हैं .गैस सिलेंडर चार सौ रुपए से ग्यारह सौ रुपए मे मिल रहा है. उज्जवला योजना ठप पड़ी है लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. इन्होंने चुनाव के समय किसानोंसे बड़े बड़े वादे किया थे किसानों की आए दुगनी करेंगे. किसान कल्याण कोष बनाएंगे. किसान आज समर्थन मूल्य के लिए दर दर भटक रहे हैं.

बजट : हकीकत से दूर और विकास विरोधी है प्रदेश का बजट

प्रदेश सरकार प्रस्तुत बजट पर विधायक सचिन यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों के पूरी तरह विपरीत और विकास विरोधी है. सरकार केवल खोखले दावों और आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए जनता को गुमराह कर रही है. प्रदेश आज बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन बजट में कोई समाधान या ठोस रोडमैप नहीं है. सचिन यादव ने कहा कि सरकार पर लगभग 74,000 करोड़ रुपये घाटे का बजट है. यह बजट आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और कमजोर करेगा. सरकार ने अमेरिका से व्यापार समझौता कर देश के किसानों की कब्र खोदी है. प्रदेश और देश के किसानों के हितों के खिलाफ है. पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए किया गया बजट आवंटन 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित हो रहा है। यादव ने कहा कि यह बजट केवल कागजी सपनों का जाल है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पाण्डे की बजट पर प्रतिक्रिया

विधानसभा में प्रस्तुत बजट को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने खोखले वादों का बजट निरूपित किया है. यह बजट प्रदेश की आम जनता के साथ छलावा है और कर्मचारी मजदूर विरोधी है. सरकार ने चार लाख अड़तीस हजार तीन करोड रुपए का बजट प्रस्तुत किया है. वहीं 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक का घाटे का बजट भी बताया है तो फिर घोषित योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? यह बजट सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन बजट में इस पर कोई स्पष्ट नीति, योजना या समयसीमा नहीं है. पाण्डेय नेकहा कि बजट में युवाओं की नौकरी और भर्ती पर चुप्पी है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी कि भर्ती, नई नौकरियों और रोजगार सृजन पर ठोस प्रावधान होंगे, संविदा भर्ती की बात कही गयी.

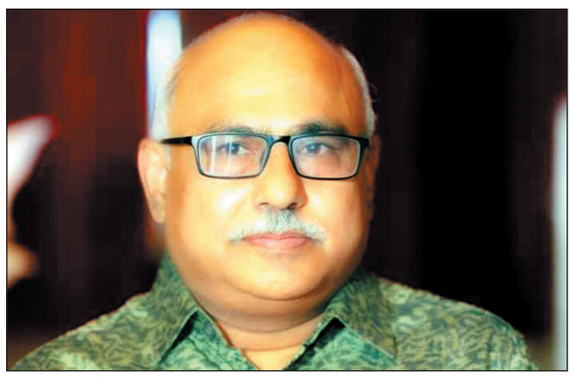

एमपी बजट ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हित में : हेमंत

भोपाल, 18 फरवरी. मध्यप्रदेश के वर्ष 226-27 के बजट को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हित में बताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत 4,38,317 करोड़ रुपये का यह बजट प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम है.

प्रति व्यक्ति आय बढ़ना राज्य के लिए बेहतर

लाड़ली बहना योजना के लिए भी बजट प्रावधान

श्री खंडेलवाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 रुपए से बढ़कर 1,69,000 रुपए हो गई है, जो सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों का परिणाम है. उन्होंने बताया कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करता है. गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और 1 लाख सोलर पंप किसानों को देने की योजना है.

प्राकृतिक खेती के लिए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य और फसल बीमा के लिए 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. महिलाओं के लिए 'लाड़ली बहना योजना' के तहत 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 5,700 महिला हॉस्टल और पेंशन व्यवस्था पर जोर दिया गया है. युवाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रावधान और खेलों के विकास के लिए 815 करोड़ रुपए तय किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मजरे-टोले की सड़कों के लिए 21,000 करोड़ रुपए, शिक्षा क्षेत्र में 294 नए विद्यालय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 472 नई ई-बस सेवाओं की शुरुआत और 1,00,000 करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय से अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी.

खंडेलवाल ने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला, संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुख बजट है.

सरकार का बजट जनता के साथ खुला धोखा

भोपाल. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए इसे 卐ठग बजट卐 बताया. उन्होंने कहा कि 4.38 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट के पीछे 78, करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा छिपा हुआ है, जिसकी स्पष्ट व्याख्या सरकार आज तक नहीं कर पाई है कि यह राशि भविष्य में कहां से लाई जाएगी.

श्री पटवारी ने कहा कि पिछले वर्ष 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, लेकिन उसका लगभग 50 प्रतिशत तक उपयोग ही नहीं हो पाया. इसके बावजूद सरकार रोज़ाना औसतन 213 करोड़ रुपये का कर्ज लेती रही. यह वित्तीय कुप्रबंधन जनता को गुमराह करने और प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने का प्रमाण है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखे शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को कुत्तों की नसबंदी की चिंता छोड़कर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की नसबंदी करनी चाहिए. तभी मध्य प्रदेश आर्थिक आपातकाल जैसे हालात से बाहर निकल पाएगा.

उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता का खून चूसने वाला बजट है. श्री पटवारी ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें कहा गया कि सरकार ने कोई नया कर नहीं बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी पर वैट के मामले में मध्य प्रदेश पहले से ही देश के सबसे महंगे राज्यों में शामिल है. क्या सरकार जनता पर और बोझ डालना चाहती है

उन्होंने कहा कि बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की बात तो की गई, लेकिन किसानों और गरीबों के साथ खुले तौर पर छल किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किसानों को सोयाबीन 6000, धान 3100 और गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीदने के वादे किए गए थे—लेकिन बजट में इनके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है.

इसी तरह लाड़ली बहनों को 3000 प्रतिमाह देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई स्पष्ट और पर्याप्त प्रावधान नहीं दिखता. विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने जैसे वादों का भी बजट में कोई ठोस उत्तर नहीं है. श्री पटवारी ने कहा कि जिस बजट में 78,000 करोड़ रुपये का घाटा स्वीकार किया गया है, उसी में पिछले वर्ष लिए गए 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज का पैसों का आवंटन हुआ पीएम आवास, मनरेगा और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य के बजट से प्रावधान कर यह स्पष्ट हो गया है कि यह राज्य का बजट कम और केंद्र शासित प्रदेश जैसा बजट अधिक बन गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट का आकार जानबूझकर बढ़ाया गया है ताकि कर्ज का मूल्यांकन बढ़े और सरकार और ज्यादा कर्ज ले सके. यह जनता को गुमराह करने की एक सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसका नकाब अब उतर चुका है.

बजट में मप्र के संपूर्ण विकास के प्रावधान

भोपाल. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है.

इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी. श्री राजपूत ने कहा कि इस बजट में मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण, युवा शक्ति,अन्नदाता, नारी शक्ति, अधोसंरचना और उद्योग पर फोकस किया है. इस बजट से प्रदेश के कृषि विकास औद्योगिक निवेश, अधोसंरचना विकास के संतुलित संयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने कि दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिये समुचित प्रावधान किये है.

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि नये बजट में अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने के लिये गरीब कल्याण की दिशा में सरकार ने अल्प आय तथा समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुये वर्ग के कल्याण के लिये ' 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान'' के तहत 793 करोड़ का प्रावधान किया है. सरदार पटेल कोचिंग योजना के तहत 4000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. वहीं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये 1 हजार 691 करोड़ का प्रावधान किया है जबकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये 2857 करोड़ का प्रावधान है. इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विगत 2 वर्षों में 5 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ का 66 लाख 25 हजार मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है. प्रदेश में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिये उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के लिये लगभग 93 प्रतिशत हितग्राहियों का ई.केवायसी किया जा चुका है. प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास का निर्माण योजना के तहत 1 हजार 235 करोड़ का प्रावधान किया है.

खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि नये बजट में प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सांदीपनी विद्यालय 3 हजार 892 करोड़ साइकिल प्रदाय योजना के लिये 210 करोड़ पीएम श्री योजना में 530 करोड़ तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

विशेष ध्यान

स्वास्थ्य क्षेत्र में 23 हजार 747 करोड़ का प्रावधान

भोपाल. 18 फ़रवरी. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को "समृद्ध मध्यप्रदेश 2047" की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी एवं परिणामोन्मुखी दस्तावेज बताया है. उन्होंने कहा कि बजट में 'ज्ञान' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) से आगे बढ़कर 'ज्ञानी' (GYANII) की अवधारणा को साकार किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त रूप से जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि बजट में शहरी, ग्रामीण हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचना विकास सभी सेक्टर के लिए प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित एवं समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है. उप मुख्यमंत्री शुक्ल कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 23 हजार 747 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 4600 करोड़ रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिए 3056 करोड़ रुपये, जिला एवं सिविल अस्पतालों हेतु 2049 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन हेतु 1934 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए 1277 करोड़ रुपये तथा राज्यांश सहित कुल 2139 करोड़ रुपये का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब एवं वंचित वर्ग को नि:शुल्क उपचार की सुविधा निरंतर मिलती रहे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में भी ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं. एमबीबीएस सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ स्नातकोत्तर सीटों का विस्तार किया गया है. निजी क्षेत्र की सहभागिता से नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं तथा हजारों चिकित्सक एवं नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा.बजट में स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण पर विशेष बल दिया गया है.

सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना तथा आधुनिक उपकरणों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी प्रदेश के रूप में मध्यप्रदेश टेलीमेडिसिन एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से उपचार की पहुंच को और विस्तारित करेगा.